

## गांवों को सड़क से जोड़ने की राह में रोड़े

संजीव मुखर्जी  
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर

देश की 65,000 रिहाइशों को सभी मौसम में चलने योग्य ग्रामीण सड़कों से 2019 तक जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए भाजपा शासित असम, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान सहित 9 राज्यों में निर्माण कार्यों को बहुत तेज करना होगा। इन राज्यों के साथ बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इन 65,000 बस्तियों की 80 प्रतिशत से ज्यादा बस्तियां आती हैं।

अधिकारियों ने कहा कि इन 9 राज्यों को समय से लक्ष्य पूरा करने के लिए निर्माण कार्यों अन्य राज्यों की तुलना में बहुत तेज करना होगा। अधिकारी ने कहा कि असम में अब प्रतिदिन करीब 2.23 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है, जबकि लक्ष्य हासिल करने के लिए रफ्तार बढ़ाकर 22 किलोमीटर प्रतिदिन करना होगा। इसी तरह से झारखंड को ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण की रफ्तार पांच गुना बढ़ानी होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में मौजूदा रफ्तार के 6 गुना रफ्तार से काम करना होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'हम धीमी रफ्तार से काम कर रहे राज्यों के साथ लगातार बात कर रहे हैं और उन्हें रफ्तार तेज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम 1 नवंबर से संपत्तियों के जियो टैगिंग के माध्यम से उनके कार्यों की निगरानी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में स्थिति में सुधार होगा।' उन्होंने कहा कि शेष सभी रिहायशों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें दिसंबर 2016 कर पूरी कर ली जाएगी। सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस्तेमाल की जाने वाली कम से कम 15 प्रतिशत सामग्री हरित तकनीक जैसे सीमेंट, कंक्रीट ब्लॉक्स फ्लाइंग ऐश, प्लास्टिक कचरा आदि के इस्तेमाल के माध्यम से हो।

कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ग्राम

### ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर

कुल निर्माण	
400,000 किमी 2000-2014	80,000 किमी 2014-2016
कुल हरित निर्माण	
800 किमी 2000-2014	2,600 किमी 2014-2016
सड़क निर्माण की संभावित गति	
170 किमी/प्रतिदिन 2018-19	अगले 3 साल में कुल खर्च 81,000 करोड़ रुपये 2016-19

सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के माध्यम से ग्रामीण सड़क निर्माण योजना में पिछले 2 साल में भारी सुधार देखा जा रही है और 2016-17 में 48,818 किलोमीटर के लक्ष्य से ज्यादा सड़कों के निर्माण की उम्मीद है।

अधिकारियों ने कहा कि इस वित्त वर्ष में करीब 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से करीब 23,45 किलोमीटर (लक्ष्य का करीब 48 प्रतिशत) सड़कों का निर्माण हो चुका है।

मंत्रालय को उम्मीद है कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण की रफ्तार 2018-19 में 170 किलोमीटर प्रतिदिन हो जाएगी, जो इस समय औसत 133 किलोमीटर प्रतिदिन है। अगले 3 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएमजीएसवाई के तहत करीब 81,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है, जिसमें से केंद्र सरकार की हिस्सेदारी करीब 57,000 करोड़ रुपये होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्ववर्ती राजग सरकार के कार्यक्रम में 2000 में शुरु की गई थी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रमुख योजना थी। योजना शुरू होने के बाद पिछले 16 साल में करीब 4,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है।

## निगमित कर में कटौती पर विचार

दिलाशा सेठ और अरुण रॉयचौधरी  
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर

वित्त मंत्रालय निगमित कर में 1 से 2 प्रतिशत अंक कटौती की संभावना पर विचार कर रहा है। राजस्व विभाग नवंबर के पहले सप्ताह से उद्योग जगत व सलाहकारों से चर्चा शुरू करने जा रहा है। यह कवायद निगमित कर वित्त वर्ष 2018-19 तक मौजूदा 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत तक किए जाने का हिस्सा है।

इस मामले से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष से निगमित कर 30 प्रतिशत से 1 से 2 प्रतिशत कम करने पर विचार कर रही है, जो चरणबद्ध तरीके से छूट खत्म किए जाने के आधार पर होगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 में वादा किया था कि निगमित कर की दरें 2019 तक घटाकर 25 प्रतिशत की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न छूटों को चरणबद्ध तरीके से खत्म किए जाने की बात कही थी, जो उद्योग जगत को मिलता है। इसमें कर की दरें कम करना, प्रशासन आसान

### बजट 2017-18 से प्रमुख उम्मीदें



- निगमित कर में 1 से 2 प्रतिशत की होगी कमी
- व्यक्तिगत कर की दरें होंगी कम
- इक्वालाइजेशन लेवी या ग्लॉबल टैक्स को व्यापक करने की संभावना

करना और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार किया जाना शामिल है। निगमित कर 30 प्रतिशत है, लेकिन यह प्रभावी रूप से 23 प्रतिशत है, क्योंकि उद्योग जगत को तमाम छूट मिलते हैं।

2016-17 के बजट में 5 करोड़ रुपये तक या इससे कम कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए निगमित कर दरें 30 प्रतिशत और अधिभार व उपकर से कम करके 29 प्रतिशत और अधिभार व उपकर कर दी गई थीं। इसके साथ ही 1 मार्च 2016 और उसके बाद से सभी

नई विनिर्माण कंपनियों के लिए निगमित कर की दरें घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा की गई थी, जिन्हें कोई दावा व छूट नहीं दिया जाना था।

बजट पूर्व चर्चा से जुड़े एक अन्य वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने कहा कि आगामी बजट में निगमित कर 1 से 2 प्रतिशत कम किए जाने को लेकर वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श चल रहा है। अधिकारी ने कहा, 'बजट की तिथि नजदीक आने तक चीजें साफ होंगी, लेकिन हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि

## जलमार्ग-1 से 4 राज्यों को लाभ

सरकार ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर विकास कार्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी तथा रोजगार सृजित होंगे।

अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास पोत परिवहन मंत्रालय का एक बड़ा प्रयास है। जल मार्ग विकास परियोजना का चरण-1 हल्दिया-वाणगंजी मार्ग को कवर करेगा। मंत्रालय ने कहा कि परियोजना में जहाज के लिए रास्ता, वाणगंजी, हल्दिया और साहेबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल, नदी नौवहन प्रणाली में मजबूती, डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रात्रि में नौवहन सुविधा आदि शामिल हैं।

## मुलायम ने कहा, एकजुट है पार्टी

बीएस संवाददाता  
लखनऊ, 25 अक्टूबर

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी परिवार में मचे घमासान के बीच सुलह का रास्ता निकालने और आपस में तलवार भांज रहे परिवारों को पटरी पर लाने के लिए आज सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव सामने आए।

मुलायम ने प्रेस वार्ता में ऐलान किया कि परिवार और पार्टी एकजुट है और उनमें किसी तरह का मतभेद नहीं है। हालांकि पार्टी मुख्यालय में मुलायम के यह ऐलान करते समय उनके साथ शिवपाल यादव तो मौजूद रहे पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नदारद थे।

इससे पहले सोमवार रात और आज सुबह मुलायम के आवास पर

### शिवपाल पार्टी चलाएंगे और अखिलेश चलाएंगे सरकार

अखिलेश और शिवपाल के साथ दो दौरे में बातचीत हुई और संकट का हल निकालने के प्रयास किए गए। मुलायम की प्रेस वार्ता के दौरान साजा जा रहा था कि शिवपाल के साथ अखिलेश भी मौजूद रहेंगे, पर उनकी अनुपस्थिति ने सुलह की कामयाबी पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है।

सपा सुप्रीमो ने साफ किया कि सरकार अखिलेश चलाएंगे जबकि संगठन शिवपाल के हवाले रहेगा। उन्होंने पार्टी महासचिव अमर सिंह पर किसी तरह की कार्रवाई से इन्कार किया जबकि रामगोपाल

किस तरह से निगमित कर 2019 तक घटाकर 25 प्रतिशत पर लाया जाए। आगामी बजट में इसी लक्ष्य के मुताबिक कटौती होगी।

2015-15 में विभिन्न छूटों पर 62,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए थे। डेलॉयल की नौरु आहूजा ने कहा कि वित्त मंत्री को दो साल पहले किए गए वादे के मुताबिक निश्चित रूप से निगमित कर में कटौती करनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'हम उनसे उम्मीद करते हैं कि इस बार निगमित कर व व्यक्तिगत करों में भी कुछ कटौती होगी।'

राजस्व विभाग की चर्चा अहम होगी, क्योंकि अगले वित्त वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), जनरल एंटी एवायडेंस एग्रीमेंट (जीएएआर), पुनरीक्षित दोहरा कराधान परिहार समझौता, बेस इरोजन ऐंड प्रॉफिट शेयरिंग (बीईपीएस) के साथ कुछ अन्य कर सुधार लागू होने हैं।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'नवंबर के पहले सप्ताह से बजट पर चर्चा शुरू रही है। उद्योग व व्यक्तिगत कर को आसान बनाने के इर्द गिर्द चर्चा केंद्रित होगी। अगले वित्त वर्ष से कर संबंधी तमाम बदलाव हो रहे हैं, ऐसे में यह चर्चा अहम है।'

**Bharat Heavy Electricals Limited**  
यूनिट: तिरुचिरापल्लि  
उपकरण की आवश्यकता  
वीएचईएल तिरुचिरापल्लि को हैंड हेल्ड विद्युत वालित ट्यूब एंड बेवेलिंग उपकरण-एंगुलर टाइप (Hand Held Electrically Operated Tube End Beveling Equipment - Angular Type) की आवश्यकता है। जिसके लिए टैंडर दस्तावेज एवं पूर्ण विवरण वीएचईएल वेबसाइट <http://www.bhel.com> (टैंडर अधिसूचना पेज) या सरकारी निविदा वेबसाइट <http://tenders.gov.in> (एलिके संकेतक यूनिट) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पेज पर सदर संख्या **NOIT 29798** या <https://bheleps.buyjunction.in> पर सदर संख्या **2631600001** से डाउनलोड किया जा सकता है।  
टैंडर हेतु सभी सुविध/परिशिष्ट/संशोधन/समायोज्य विस्तार/सम्प्रीकरण आदि केवल उपरोक्त वेबसाइट पर प्रकाशित किए जायेंगे अन्य किसी भी माध्यम द्वारा प्रकाशित नहीं किए जायेंगे। बोटीदाता स्वयं को अपडेट करने हेतु नियमित रूप से उपरोक्त वेबसाइट देखें।  
DGM / MM / CE, BHEL, Tiruchirappalli - 620 014.  
Ph.: +91-431-257 7653 / 7830; email: [skaruna@bheltry.co.in](mailto:skaruna@bheltry.co.in)

**PUBLIC NOTICE**  
**Atria Energy Services Pvt. Ltd.**  
1<sup>st</sup> Floor, No-11, Commissariat Road, Bangalore 560025  
**Notice under sub-section (2) of Section 15 of the Electricity Act, 2003**  
1. The person above-named, a company incorporated under the Companies Act, 2013 has made an application under sub-section (1) of Section 15 of the Electricity Act, 2003 for grant of Category IV license for inter State trading in electricity in Pan India before the Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi. The necessary details in respect of the applicant are given hereunder:  
i) Authorized, issued, subscribed and paid-up capital.  
ii) Shareholding Pattern  
iii) Financial and technical strength- Mr. D. V. Kishore, Finance Head is a Sr. Management professional with experience of over 19 years in Renewable Energy, IT and Telecom in the areas of PE and Debt raising, Strategy, Risk Management, accounting, audit, reporting, MIS, commercial and corporate finance, business management, treasury, budgeting, FP&A  
iv) Management profile of the applicant including details of past experience of the applicant and/or the persons on the management of the applicant in generation, transmission, distribution and trading of electricity or similar activity. Mr. K. Nagaraju, Director, sets the direction for management committee, plays a pivotal role in creating the vibrant culture, and leads the thinking on what Electricity can offer to the society through Atria's vision. Other than power, his endeavours under the Atria Group include ventures in Hospitality, Real Estate, and Information Technology.  
Mr. Amit Kumar, HOD [B.E & M.B.A (Power), NPFI, Faridabad] is a seasoned professional with special experience in Power Trading & Renewable Energy with over 13yrs of business analyst & techno-commercial experience of working across domains, with different stakeholders in SAARC Electricity markets.  
v) Volume of electricity intended to be traded during the fast year after grant of licence and future plans of the applicant to expand volume of trading - As allowable under category IV.  
vi) Geographical areas within which the applicant will undertake trading in electricity - Pan India. Net worth as on 31st March of three consecutive years, immediately preceding the year of application or for such lesser period as may be applicable and on the date of the special balance sheet accompanying the application:- Rs. 1,85,16,842/-  
viii) Year-wise current ratio and liquidity ratio of the applicant for three years preceding the year in which the application is made, or for such lesser period as may be applicable and on the date of the special balance sheet accompanying the application:- 1:0  
ix) (a) A statement whether the applicant is authorized to undertake trading in electricity under the Memorandum of Association or any other document - Yes  
(b) If so, reproduce the specific provision of Memorandum of Association or any other document so authorizing trading in electricity - "To establish and carry on the businesses of generators, suppliers, processors, accumulators, distributors, transmitters, traders, converters of and dealer in, and the sale and purchase of electricity and electrical energy in any form"  
x) Details of cases, if any, where the applicant or any of his associates, or partners, or promoters, or Directors has been declared insolvent and has not been discharged - None  
xi) Details of the cases, if any, in which the applicant or any of his associates or partners or promoters or Directors has been convicted of an offence involving moral turpitude, fraud or any economic offence during the previous three years preceding the year of making the application and the year of making of applicant and the date of release of the above person from imprisonment, if any, consequent to such conviction - None  
xii) Whether the applicant or any of his associates, or partners, or promoters, or Directors was ever found guilty in any proceedings for contravention non-compliance of any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made thereunder or an order made by the Appropriate Commission, during the year of making the application or five years immediately preceding that year? - No  
2. The application made and other documents filed before the Commission are available for inspection by any person with Mr. Amit Kumar, Chief Marketing Officer, 1st Floor, No-11, Commissariat Road, Bangalore 560025. Phone: 080-4941149. Email: [amit.kumar@atriapower.com](mailto:amit.kumar@atriapower.com)  
3. The application made and other documents filed before the Commission have been posted on [www.atriapower.com](http://www.atriapower.com)  
4. Objections or suggestions, if any, on the application made before the Commission may be sent to the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, 3rd & 4th Floor, Chandernagore Building, 36, Jangpeth, New Delhi-110001, Ph: +91-11-23355303, Fax: +91-11-23375323 (Give the address where office of the Commission is situated) within 30 days of publication of this notice, with a copy to the applicant.  
5. No objections or suggestions shall be considered by the Commission, if received after expiry 30 days of publication of this notice.  
Place: Bangalore  
Date: 26th October, 2016  
Amit Kumar, Chief Marketing Officer  
(Authorised Signatory)

**SHRIRAM Commercial Vehicle Finance GETS YOU GOING**  
**SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LIMITED**  
Corporate Identity No. (CIN): L65191TN1979P0007874  
Regd. Office: Mookambika Complex, 3<sup>rd</sup> Floor, No. 4, Lady Desika Road, Mylapore, Chennai - 600 004.  
Tel No: +91 44 2499 0356, Fax: +91 44 2499 3272, Website: [www.stfc.in](http://www.stfc.in), Email Id: [secretarial@stfc.in](mailto:secretarial@stfc.in)

**Extract of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Half year ended September 30, 2016** ₹ in lacs

Particulars	Quarter Ended 30.09.2016	Half Year Ended 30.09.2016	Quarter Ended 30.09.2015
Total Income from operations (net)	271,320	539,989	242,353
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	38,765	76,175	33,810
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	38,765	76,175	33,810
Paid-up equity share capital (face value ₹ 10/- per share)	22,691	22,691	22,691
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	992,721 (as on March 31, 2016)	992,721 (as on March 31, 2016)	901,106 (as on March 31, 2015)
Earnings per share (before and after extraordinary items) (of ₹ 10/- each)			
Basic (₹)	17.08	33.57	14.90
Diluted (₹)	17.08	33.57	14.90

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Half yearly Financial Results are available on the stock exchange websites: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and company's website: [www.stfc.in](http://www.stfc.in).

By order of the Board  
For Shriram Transport Finance Company Limited  
Jasmit Singh Gujral  
Managing Director & CEO  
DIN: 00196707

Place : Mumbai  
Date : October 25, 2016

**ORTEL COMMUNICATIONS LIMITED**  
Registered Office: B7/1122A, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110029  
Corporate Office: C-1, BDA Colony, Chandrasekharpur, Bhubaneswar, Odisha - 751016 Phone: 0674-3983200. Mail Id: [ipo@ortelgroup.com](mailto:ipo@ortelgroup.com)  
CIN: L74899DL1995PLC069353  
**Extracts of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2016** Rs. in lakhs

Particulars	Quarter Ended 30-Sep-16	Half Year Ended 30-Sep-16	Quarter Ended 30-Sep-15
	Unaudited	Unaudited	Unaudited
Total Income from Operations (Net)	5,372.87	10,614.54	4,578.79
Net Profit/(Loss) from Ordinary activities after tax (before extraordinary item)	254.27	340.20	283.11
Net Profit/(Loss) from Ordinary activities after tax(after extraordinary item)	254.27	340.20	283.11
Equity Share Capital	3036.54	3036.54	3036.54
Reserve (excluding Revaluation reserve as shown in the Balance sheet of previous year)			
Earning Per Share (EPS) (before and after extraordinary item) of Rs. 10/- each:			
a) Basic	*0.84	*1.12	*0.93
b) Diluted	*0.83	*1.12	*0.93

\* Not Annualised

**Note:**  
1. The above is an extract of the detailed format of the standalone financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said standalone financial results are available on Stock Exchange Websites ([www.bseindia.com/](http://www.bseindia.com/) [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com/)) and Company's website: [www.ortelcom.com](http://www.ortelcom.com)  
2. The above result have been subject to "Limited Review" by Auditors of the Company and have been reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 25 October 2016.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Bhubaneswar  
Date : 25.10.2016  
Sd/  
Managing Director

## कैबिनेट कर सकता है केयरन इंडिया के बाइमेर विस्तार पर फैसला

शाइन जैकब  
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर

केयरन इंडिया और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के बीच बाइमेर तेल एवं गैस ब्लॉक से उत्पादन में हिस्सेदारी समझौते (पीएससी) को 10 साल तक विस्तार दिए जाने पर कैबिनेट जल्द फैसला कर सकती है। बाइमेर परियोजना राजस्थान में

है, 2020 तक के लिए इस पर समझौता हुआ है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार मंजूरी के लिए 28 नेल्य (नई अन्वेषण लाइसेंस नीति) के पहले के 28 अन्वेषण ब्लॉकों पर विचार करेगी, जिसमें बाइमेर ब्लॉक भी शामिल है। इस ब्लॉक को राजस्थान ब्लॉक के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य और

राशेखरी तेल एवं गैस क्षेत्र शामिल हैं। यह भारत का सबसे बड़ा ऑनशोर तेल उत्पादन परियोजना है, जहां रोजाना 1,66,000 बैरल के करीब तेल का उत्पादन होता है। यह भारत में होने वाले कुल तेल उत्पादन का 27 प्रतिशत है।

इस साल मार्च में कैबिनेट ने 28 छोटे व मझोले आकार के खोजे गए क्षेत्रों के विस्तार को मंजूरी दी

थी। सूत्रों के मुताबिक खोजे गए क्षेत्रों को विस्तार के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाना है, ऐसे में खोजे गए ब्लॉकों के लिए भी कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, 'इस पर हमने अब तक अंतिम फैसला नहीं किया है। लेकिन संभावना है कि इन 28 ब्लॉकों के विस्तार के मामले को भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाए। इनमें

से 10-11 उत्पादक क्षेत्र हैं।' राजस्थान ब्लॉक में केयरन इंडिया की 70 प्रतिशत, जबकि ओएनजीसी की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आरजे-आन 90/1 का विस्तार बाइमेर के पश्चिम 3,111 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। केयरन इंडिया के मुताबिक बाइमेर ब्लॉक के पीएससी विस्तार से 25 करोड़ बैरल के बराबर उत्पादन और होने लगेगा।

## बीएस सूडोकू 2645 | परिणाम संख्या 2645

5	7		4			9
1	9		2	7		6
	6					3
		6	1	9		
			6	2		
			5	7	8	
2						5
6			9	8	1	2
3			2			9

9	1	8	5	7	2	6	4	3
4	6	2	8	3	1	5	9	7
3	5	7	4	9	6	8	1	2
2	3	5	9	4	7	1	6	8
8	7	1	2	6	5	4	3	9
6	4	9	3	1	8	2	7	5
1	8	6	7	5	9	3	2	4
7	2	4	1	8	3	9	5	6
5	9	3	6	2	4	7	8	1

### कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर जौ तक की संख्या भरें।

### मध्यम

★  
★  
★  
★  
★

## क्षेत्रीय मंडियों के भाव

बंद भाव रुपये प्रति क्विंटल  
**दिल्ली**  
अनाज : गेहूँ म.प्र. (देशी) 2340-2875, गेहूँ दूध फ्लोर मिल 1900-1905, चक्की आटा (डिलिवरी) 1910-1915 (90 किगो), आटा राजधानी (10 किग्रा) 275, शक्तिभोज (10 किग्रा) 275, सेलर फ्लोर मिल 1010-1015 (50 किग्रा), मैदा 1100-1110 (50 किग्रा) और सूजी 1210-1215 (50 किग्रा), चासमती चावल लाल किला 10700, श्रीलाल महल 11300, सूपर चासमती चावल 9700, चासमती चावल नई 5200-5300, चावल पूसा (1121) 4400-5300, परमल कच्चा 2050-2075, परमल वैन्ड 2150-2200, सेला 2800-2900 और चावल आईआर-आर 1850-1860, बाजरा 1300-1305, ज्वार पीला 1750-1800, सफेद 3400-3600, मक्का 1510-1510, जौ 1630-1635, दलहन : उड़द 7450-9050, उड़द छिलका

स्थानीय 7900-8000, उड़द सर्वोत्तम 8000-8500, घोया 8400-8700, मूंग 5400-6000, दाल मूंग छिलका (स्थानीय) 5900-6200, मूंग घोया स्थानीय 6500-7000 और बेहतरीन क्वालिटी 7000-7200, मसूर छोटी 5500-5700, बोल्ड 5550-5750, दाल मसूर स्थानीय 5950-6450, बेहतरीन क्वालिटी 6050-6550, मलका स्थानीय 6400-6900, बेहतरीन 6500-7000, मोठे 4200-4500, **कानपुर**  
गेहूँ 1860/1865, जौ 1625/1630, चावल मसूर 2050/2150, चावल मोटा 1950/2000, सरसों 4250/4350, तिल सफेद 6100/6200, सोया (टीन) 1050/1090, तेल सरसों कच्ची घानी बेट पेड (टीन) 1460/1570, सरसों खल 2400/2425, पामोलिन 1040/1050, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 1015/1025, अलसी खल 3250/3375, **लखनऊ**

अनाज एवं दाल-दलहन: गेहूँ दड़ा 1900/1910, गेहूँ शरबती 2650/2800, चावल सेला शरबती 2800/3025, लालमली 2350/2400, चावल (सेला) 2075/2140  
**चंडीगढ़**  
(प्रति किलो): मैन्वा ऑयल 980, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.) 1100, फ्लैक 1050, डीएमओ 730, टर्पीन लैस बोल्ड 1120 गुड़ (40 किगो): चाकू 1050/1170, खुरपा 1050/1100, ल